राजनीति मे नैतिकता का प्रभाव

वर्ष 2014 भारतीय राजनीति में दो उत्कर्षों के लिए याद किया जायेगा–

(1)स्वतंत्रता के तत्काल बाद राजनीति में नैतिकता के पतन की हुई शुरुवात का 2014 के पूर्वाध में चरमोत्कर्ष।

(2)2014 के उत्तरार्ध में नैतिकता के उत्थान की सम्भावना का प्रारंभ।

पिछले वर्ष अनेक राजनेताओं ने नैतिक पतन के कीर्तिमान स्थापित किये। चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हार जाने के कारण सरकारी बंगला छोड़ने का आदेश हुआ। नैतिकता के आधार पर उन्हें बिना नोटिश मिले ही बंगला छोड़ देना चाहिए था। किन्तु अजीत सिंह ने तो ऐसा कीर्तिमान बनाया कि पुलिस द्वारा सामान बाहर फेंक देने के बाद भी उन्होने मकान का मोह नही छोड़ा। वे इतना नीचे उतर गये कि उन्होने मकान पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने पिता चरण सिंह के नाम का उपयोग किया। विदित हो कि चरण सिंह किसान होते हुये भी एक इमानदार राजनेता स्थापित रहे तथा प्रधानमंत्री भी बने। दुख होता है कि उन्ही चरण सिंह का बेटा एक मकान पर कब्जा करने के लिए अपने इमानदार पिता के नाम का उपयोग करे। हद तो तब हो गई जब अजीत सिंह ने फिर से मकान पर कब्जा करने के लिए आन्दोलन छेड़ दिया और जंतर मंतर पर कुछ समर्थकों को इकट्ठा कर दिया। सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया और चरण के नाम पर मकान के दुरुपयोग के समक्ष झुकने से इन्कार कर दिया। सम्पूर्ण देश में अजीत सिंह के इस प्रयत्न की भरपूर आलोचना हुई। किन्तु कुछ राजनेता फिर भी उनके पक्ष में खड़े होने में सफल हो गये। अजीत सिंह ने आज तक नैतिकता के तराजू पर अपने इस कार्य को तौलने का प्रयास नही किया।

2014में ही हरियाणा के चुनाव आये। हरियाणा के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद दस वर्षों के लिए जेल में चले गये। जेल में रहते हुए ही उन्होने बीमारी के इलाज के नाम पर पैरोल मॉगा और ठीक चुनाव के समय बाहर आने में सफल हो गये। विदित हो कि श्री चौटाला हरियाणा के उस सम्मानित देवीलाल के पुत्र है जिन्होने प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद भी इन्कार कर दिया था। ओमप्रकाश चौटाला ने सारी शालीनता छोडते हुए खुला चुनाव प्रचार शुरु कर दिया और तब तक चुनाव प्रचार में लगे रहे जब तक न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उन्हे जेल जाने के लिए मजबूर नही कर दिया। ओमप्रकाश चौटाला ने कभी जेल जाने के कारणो की समीक्षा नही की, कभी पश्चाताप नही किया,कभी शर्मिंदा नही हुए, बल्कि अब भी सीना तानकर राजनीति का व्यवसाय करने में लगे हुए है।

यदि हम तमिलनाडु का उदाहरण देखे तो वहॉ की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी एक कीर्तिमान ही बनाया। जयललिता को आय से अधिक सम्पत्ति मामलों मं न्यायालय से सजा हुई और वे जेल पहुॅचा दी गई। आरोप सिद्ध होने के बाद भी उन्होने शर्मिंदा होने की कोई पहल नही की। इसके विपरीत उन्होने यहॉ तक तिकड़म की, कि वे जेल से ही मुख्यमंत्री का काम चलाती रहे। विदित हो कि जयललिता पुर्व मुख्यमंत्री ,एम जी रामचन्द्रन को निकट की मित्र रही है। आश्चर्य तो तब हुआ जब जयललिता ने राजनैतिक दबाव बनाने के लिए तमिलनाडु में हड़ताल कराने का सहारा लिया। यह हड़ताल चरम पर पहुॅची जब इनके कई सर्मथकों ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की। जय ललिता ने भी कभी नैतिकता का मानदंड नही अपनाया।

इसके पुर्व भी हम ऐसे ही भ्रष्टाचार का नाटक बिहार में देख चुके है। बिहार में लालूप्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा। ये वही लालू प्रसाद यादव है जो जयप्रकाश नारायण के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। इन्हें भी जेल से सरकार चलाने का अच्छा अनुभव प्राप्त है। इन्होने जेल जाते समय अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर स्वयं सारा संचालन करते रहे। 2014 के वर्ष में उन्हें भी जब दण्ड सुनाया गया तो लालू जी ने मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव डालकर कानून में फेर बदल कराने की भरपूर कोशिश की। यदि एकाएक राहुल गॉधी की आत्मा न जगी होती तो लालू प्रसाद की सजा भी निष्प्रभावी हो सकती थी। इस तरह राजनीति मे नैतिकता का पतन लगातार होता गया और ऐसे पतन के चरमोत्कर्श मे न जाति का भेद रहा न स्त्री पुरूष का और न ही किसी क्षेत्रीयता का और न ही राजनैतिक भेद भाव का।

स्वतंत्रता के बाद लगातार राजनीति में नैतिकता का पतन होता गया। प्रारंभ में जवाहर लाल नेहरु ने राजनीति में दस पॉच प्रतिशत अनैतिकता की शुरुवात की तो 2014 आते आते अजीत सिंह, लालू प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला, जयललिता सरीखे लोगों ने राजनीति में अनैतिकता का ग्राफ कहॉ तक पहुॅचा दिया यह बताना कठिन है। हर वर्ष ऐसा लगता था जैसे उस वर्ष राजनीति का सम्पूर्ण पतन हो गया हो किन्तु अगले वर्ष पतन की सीमायें टुटती थी और नयी सीमायें बन जाया करती थी । मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में राजनीति में नैतिकता को बचाने का भरपूर प्रयास किया किन्तु वे खडाउं प्रधानमंत्री होने के कारण अपनी नैतिकता अपने पास तक सीमित रखने के लिए मजबूर हो गये। ऐसे ही समय में दो हजार चौदह के उतरार्ध में नरेन्द्र मोदी का उदय हुआ। चुनावों के पूर्व ऐसा नही लगता था कि पतन के पाताल तक गई हुयी राजनीति पर जल्दी कोई विराम लग पायेगा किन्तु छः महिने के कार्यकाल में ही यह स्पष्ट दिखने लगा कि यदि दृढ़ निश्चय हो और परिस्थितियॉ भी अनुकूल हो तो पतन की पराकाष्ठा को बदला जा सकता है। नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आते ही हवा में कुछ ऐसी गर्माहट दिखने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के ढके चुके पदलोलुप,धनलोलुप, राजनेता भी इमानदार बनने तथा रहने के लिए मजबूर हो गये। यद्यपि नरेन्द्र मोदी ने विकास का नारा दिया था किन्तु चरित्र पतन के मामले में भी उनकी भावभंगिमा ने कमाल का परिवर्तन किया। भ्रष्टाचार करने वाले राजनेता छुपछुप कर भी भ्रष्टाचार करने में डर रहें है। अनैतिकता के बनते हुए कीर्तिमान अब नैतिकता के कीर्तिमान बनाने के लिए आतुर दिख रहें है। उम्मीद नही थी कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ संकेत दिखने लगेगा किन्तु सच्चाई यह है कि संकेत दिखने लगा है। मैं मानता हूॅ कि इस दिखने के पीछे नरेन्द्र मोदी को मिला पुर्ण बहुमत का परिस्थिति जन्य सहारा भी है। किन्तु मैं नही मानता कि इस सफलता मे मोदी की कार्यशैली की सफलता का योगदान न हो। मैं यह भी मानता हूॅ कि नरेन्द्र मोदी की नैतिकता के मामले में मिलने वाली सफलता में उनके सहयोगी संघ की छवि भी काम आयी। विदित हो कि संघ अब तक एक ऐसा संगठन है जिनके कार्यकर्ताओं की नैतिकता तथा भ्रष्टाचार के सम्बंध में कोई प्रश्न चिन्ह नही लगाया जा सकता । 2014 का उत्तरार्ध 1947 से 2014 के पूर्वाद्ध तक की नैतिक गिरावट को रोकने की शुरुवात करने में मील का पत्थर साबित हागा।

मैं मानता हूॅ कि नरेन्द्र मोदी बहुत ठीक गति से आगे बढ़ रहे है। लेकिन मैं देख रहा हूॅ कि अभी तक सामाजिक उच्श्रृंखलता में कमी नही आयी है। हर बात पर तोड़फोड़ और आग लगाने जैसी घटनायें निरंतर हो रही हैं। न सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने में काई कमी आ रही है न व्यक्तिगत सम्पत्ति के नुकसान में। जिस तरह नरेन्द्र मोदी का मुॅह देखकर ही नेताओं के नैतिकता के मापदण्ड बदल गये उसी तरह इस तोड़ फोड़ की प्रकृति पर भी रोक लगाने के लिए मोदी जी को आगे आना चाहिए। यदि एक बार एक अध्यादेश लाकर मोदी जी घाषित कर दे कि किसी भी रुप में किसी भी कारण से यदि किसी की व्यक्तिगत या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचेगा तो बिना उसके कारणों के औचित्य पर विचार किये ही उक्त सम्पत्ति की वसूली नुकसान करने वाले से की जायेगी। एक भाषण देकर यदि मोदी जी ऐसा अध्यादेश पारित कर दे तो मुझे विश्वास है कि उस दिन से यह उच्श्रृंखलता समाप्त हो सकती है। मैं जानता हूॅ कि ऐसा करने में संघ परिवार मोदी जी का सहायक नही होगा क्योकि उनके खुद के लोग ऐसी तोडफोड को प्रोत्साहित करने में संलग्न पाये जाते है। फिर भी यदि मोदी जी चाहंगे तो संघ परिवार ऐसी सहमति देने को तैयार हो सकता है। मैं यह भी जानता हूॅ कि मोदी जी से दो वर्षों में जो कुछ करने की उम्मीद की गई थी उतना उन्होने छः महिने में ही कर दिखाया है और उनसे और कुछ मॉग करना उचित नही माना जायेगा, किन्तु यह भी सही है कि कार्य करने वाले से ही कुछ उम्मीद जगती है। निकम्मों से कभी कोई मॉग करने का औचित्य नही है। यही सोचकर मैने मोदी जी से यह उपेक्षा की है। मुझे उम्मीद है आज नही तो कल मोदी जी इस दिशा में भी कदम बढ़ायेगें।

(1)नरेन्द्र सिंह जी प्रवक्ता व्यवस्थापक, बुलन्दशहर,यु0पी0 ज्ञानतत्व–8442

मैं ए टू जेड न्यूज चैनल पर आपके विचार सुनता रहा हूॅ। ऐंकर रामवीर श्रेष्ठ आपका परिचय कराते समय आपको मौलिक चिन्तक कहकर संबोधित करते हैं। आप बताइये कि विचारक ,चिन्तक तथा मौलिक चिन्तक में क्या फर्क है? यह भी बताइये कि आपमें ऐसी क्या विशेषता है कि आपके चिन्तन को मौलिक कहा जा सके?

उत्तरः– मैं निश्चित रुप से नहीं कह सकता कि तीनों शब्दों के अर्थों में क्या फर्क है।रामवीर जी श्रेष्ठ ने क्या फर्क देखा यह वे ही बता सकते हैं। फिर भी विचार मंथन के उद्देश्य से मैं अपना विचार रख रहा हूॅ।

विचारक वह होता है जो किसी विषय पर उस समय प्रचलित धारणाओं पर चिन्तन करके कुछ निष्कर्ष निकालता है। विचारक के निष्कर्ष देश काल परिस्थिति आधारित होते हैं तथा देश काल परिस्थिति बदलते ही बदल भी सकते हैं। चिन्तक हमेशा आत्म केन्द्रित होता है तथा देश काल परिस्थिति अथवा विभिन्न स्थापित विचारों की समीक्षा न करके कोई मौलिक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य को ही अनुसंधान या रिसर्च भी कह सकते है।यदि कोई चिन्तक अनेक विषयों पर मौलिक चिन्तन करके एक से अधिक विषयों पर ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जो उक्त विषय पर उस समय तक की स्थापित धारणाओं से भिन्न हो तथा विश्व स्तर पर जिसे कोई चुनौती न हो उसे मौलिक चिन्तन तथा उक्त व्यक्ति को मौलिक चिन्तक कह सकते है।

मैने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नये निष्कर्ष दिये हैं जो देशकाल परिस्थिति अनुसार ग्राहय हो सकते हैं किन्तु विश्व स्तरीय नहीं हैं। मैने परिवार की एक नई संरचना बताई है। मैने यह भी कहा है कि कन्या भ्रूण हत्या या महिला सशक्तिकाण प्रचार हानिकार है तथा समाज को महिला पुरुष में तोड़कर समस्याओं का विस्तार करेगा। मैंने भारत में महंगाई घटते जाने की बात कही है तथा यह भी कहा ह कि मंहगाई बढ़ने का हल्ला श्रम शोषण के उद्देश्य से बुद्धिजीवियों तथा पुॅजीपतियों का षड़यंत्र हैं। मैंने व्यक्ति और नागरिक को भी अलग अलग पहचान देकर उनके अधिकार परिभाषित किये हैं।मैने गुण प्रधान धर्म और पहचान प्रधान धर्म के साथ साथ धर्म और संगठन के बीच भी फर्क किया है। मने यह भी स्पष्ट किया है कि मुसलमान साम्यवादी तथा संघ परिवार का काम करने का तरीका एक है।मैने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवियों,पॅूजीपतियों तथा मिडिल क्लास का एकाधिकार है।ये लोग श्रम शोषण के उद्देश्य से कृत्रिम उर्जा को सस्ता बनाकर रखते है। इस तरह की अनेक राष्ट्र स्तर की ऐसी बाते हैं जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया है।

इनके साथ साथ मैने अनेक विश्व स्तरीय निष्कर्ष भी दिये हैं जिन पर विचार मंथन जारी है। किन्तु कम से कम तीन विश्वस्तरीय ऐसे निष्कर्ष हैं जो पहली बार प्रस्तुत किये गये हैं तथा जिन्हें आज तक न तो किसी ने चुनौती दी है न ही पूर्व स्थापित बताया है। ये तीन निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

(1)अपराध––व्यक्ति के मालिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध है। (1) चोरी, डकैती, लूट (2) बलात्कार (3)मिलावट,कमतौल (4)जालसाजी,धोखाधड़ी (5)हिंसा,बलप्रयोग, आतंकवाद।अपराध कहे जाने वाले अन्य अनेक कार्य गैर कानूनी या असामाजिक तो हो सकते हैं किन्तु अपराध नहीं।

(2)संविधान–राज्य के अधिकतम तथा समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमायें निश्चित करने वालें दस्तावेज को संविधान कहते है।राज्य के न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमायें निश्चित करने वाला दस्तावेज कानून होता है।

(3) मूल अधिकार– व्यक्ति के वे प्रकृति प्रदत्त अधिकार जिन्हें राज्य सहित कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति में तब तक कोई कटौती न कर सकें जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के वैसे ही अधिकारों का उल्लंघन न किया हो।इस तरह संविधान मौलिक अधिकार देता नहीं बल्कि व्यक्ति को मूल अधिकारों की गारंटी मात्र देता है।

मुझे लगता है कि इन तीन विश्व स्तरीय मौलिक परिभाषाओं तथा कुछ अन्य विचारों से प्रभावित होकर ही ऐंकर रामवीर जी चर्चा में मुझे मौलिक चिन्तक कह कर संबोधित करते है।

(2)राम देव प्रसाद शर्मा, खगड़िया बिहार ज्ञानतत्व 22678

ज्ञान तत्व 16–30 नवम्बर 14 अंक में हिन्दु,मुसलमान,भारत,पाकिस्तान आदि विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके पूर्व तिलक दहेज, भारतीय संविधान, शासन, महात्मा गॉधी,अम्बेड़कर इत्यादि पर बराबर चर्चा होती रही है।मैं भी अपना विचार लिखने लगा तो वह पद्यमय बन गया,यथार्थ मे ज्ञान तत्व की विधा गद्य है। मेरे विचार से मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि गॉधीवाद ही है। ईश्वर के बाद अस्थि मॉस शरीर धारी मानव कल्याणकारी अगर कोई व्यक्ति है, तो वह है महात्मा मोहन दास कर्मचन्द गॉधी । ऐसा ही विचार महान वैज्ञानिक आइन्सटाईन का भी रहा है। इसी विचार का धुरी में रखकर रचना अलग से बुक पोस्ट से भेज रहा हूँ,जिसका शीर्षक है–नाम बदनाम न कर इन्सान बन। इन्सान बन शीर्षक में अंकित करने की कृपा करेंगें जो छूट गया है। लिफाफा साट देने के बाद अन्तिम दो पक्तियों में भी सुधार किया गया है, जो इस प्रकार है न बन भगवान न दानव पर अवश्य इन्सान बन,हाथ मिला चरण सिर झुका कर परस्पर नमन । इसे भी सुधार करने की कृपा करेंगे।

उत्तरः—समाज में व्यक्ति चार प्रकार के होते है–(1)विचारक(2)सुरक्षा कर्ता(3)व्यवस्था कर्ता (4) श्रमिक।

पुराने जमाने में पहले को ब्राहमण, दूसरे को क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य तथा चौथे को शुद्र कहते थे। विचारक के लिए यह आवश्यक था कि वह मृत महापुरुषों के विचार बिना चिंतन किये कभी भी अक्षरशः न ग्रहण करे न समाज को दे। अन्य तीन वर्ण परिस्थिति तथा अपनी योग्यतानुसार महापुरुषों का अनुकरण भी कर सकते थे। मैं मानता हूँ कि महात्मा गॉधी ऐसे महापुरुषों में है जिनके विचार तब तक अनुकरणीय है जब तक कोई अन्य महापुरुष समाज में स्थापित न हो जाये किन्तु मैं गॉधी के विचार उनके जाने के बाद विचारकों के लिए बिना चिन्तन मनन के ही अक्षरक्षः स्वीकार करने अथवा प्रचारित करने के विरुद्ध हूँ। गॉधी स्वयं एक विचारक थे। यदि उन्होने भी स्वतंत्र विचार मंथन छोड़कर स्वामी दयानन्द,विवेकानन्द,गोखले या तिलक का अक्षरशः अनुकरण किया होता तो न देश को स्वतंत्रता में उनका निर्णायक नेतृत्व हो पाता न ही गॉधी स्वयं को गॉधी ही सिद्ध कर पाते।आज के गॉधीवादियों में यदि कोई विचारक शामिल रहा होता तो वह स्वतंत्रता के पूर्व बताये गये गॉधी मार्ग का अन्धानुकरण करने की अपेक्षा उस मार्ग की दिशा खोजने का प्रयत्न करता जो वर्तमान देशकाल परिस्थिति में यदि गॉधी होते तो करते।

वर्तमान समय में गॉधी के बाद कोई गंभीर विचारक स्थापित नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में राजनेता,व्यवसायी या श्रमिक आज भी गॉधी मार्ग को ही अन्तिम माग माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग गॉधी माग का बिना विचारे अनुकरण भी करें तो गलत नहीं किन्तु मैं एक विचारक हूँ तथा संभवतः आप भी होंगे। हमें विचारकों के समान पूर्व के महापुरुषों के विचारों की समीक्षा करके ही समाज को दिशा देनी चाहिये।मेरे विचार में आज विचारको का अभाव हो गया है। ज्यों ही किसी बालक में स्वतंत्र चिन्तन की प्रतिभा दिखती है त्यों ही स्थापित संगठन उनका ब्रेनवाश करके अपने साथ जोड़ने का भरपूर प्रयत्न करने लगते हैं। विचारकों का अभाव समाज के समक्ष एक खतरनाक संकट है। हमें मिलजुलकर इस संकट का समाधान निकालना चाहिये।

आपकी रचना मिली। मैने पढ़ा। पूरी रचना में कोइ ऐसा वाक्य नहीं मिला जो विवादग्रस्त हो या असत्य हो। ज्ञान तत्व विचार प्रसार की पत्रिका न होकर विचार मंथन तक सीमित है। यह पत्रिका भावनात्मक निष्कर्षों की समीक्षा करके वैचारिक धरातल देती है। आपकी रचना विचार मंथन के लिये उपयोगो न होने से न छापना मेरी मजबूरी है। व्यवस्थापक अर्थात व्यवस्था परिर्वतन अभियान कमेटी का कार्यालय भी ज्ञानतत्व कार्यालय से ही संचालित होता है किन्तु व्यवस्थापक के विचार या कार्यक्रम भी ज्ञानतत्व के उत्तरार्ध में ही जाते है, पूर्वार्ध मं नही क्योकि ज्ञानतत्व का पूर्वार्ध विचार मंथन तक सोमित होता है।

3 चद्रशेखर धर्माधिकारी, नवनीत हिन्दी, डाइजेस्ट, दिसम्बर 2014

विचार —एक चित्रकार सुन्दरता की खोज करते करते जब थक कर घर लौटा तो उसे घर में ही सुन्दरता का खजाना प्राप्त हुआ जहॉ उसे श्रद्धा के रुप में बालक, प्रीति के रुप में पत्नी तथा माता पिता के सम्पर्क से शान्ति मिली। चित्रकार ने माना कि घर ही वह एकमात्र पाठशाला है जहॉ एक ही स्थान पर सुन्दरता के अलग अलग रुप एक जगह दिख सकते हैं।

रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है–''मेरा घर मेरा यक्ष मंदिर, पूजा स्थान, अतिथिगृह और सुरक्षा का प्रेममय किला सब कुछ है, इसे ही तो घर कहते है, ''क्या ऐसा घर फेसबुक पर या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से दिखाई दे सकता है? पारिवारिकता या कौटुम्बिक भावना पर आधारित समाज रचना के सामने यही आज का यक्ष प्रश्न है जो भारतीय संस्कृति और मानवीय मुल्यों के सामने की चुनौती है और 'हाउस' और 'होम' में का यही फर्क भी है। 'घर' शब्द का अर्थ'भवन' शब्द से कही अधिक है। मकान रहने का स्थान है और घर प्रेम करने का ! सरकारें 'भवन'बना सकती है पर 'घर' तो कवल लोग ही बना सकते है और हमारे देश की मजबूती हमारे लोगों के चरित्र में ही निहित है जो कि अपने 'मकानों' को घर बनाना चाहते है। क्या यह साधन फेसबुक या अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों से हासिल हो सकेगा? कुछ अर्सा पहले मैं जापान की राजधानी टोकियो में महात्मा गॉधी की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। वापसी में हांगकांग में हवाई अड्डे पर साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार पढ़ने में आया। उसमें इन साइट शीर्षक से कुछ लेख छपे थे। एक लेख का शीर्षक था– 'लॉस्ट कनेक्शन' इस लेख में हांगकांग में ट्टते परिवार और कौटुम्बिक भावना के विनाश पर टिप्पणी की गयी थी और स्पष्ट रुप से कहा गया था कि इसका पमुख कारण फेसबुक है। इसी संदर्भ में पश्चिमी देशों के अखबारों में यह शिकायत की गयी है कि फेसबुक के कारण सीधे सम्पर्क समाप्त हो रह हैं और नकारात्मक भावना का विकास हो रहा है। इतना ही नहीं यह तलाक की बढ़ती संख्या का प्रमुख कारण है।

ब्रिटेन की संस्था डाइवोर्स ऑन लाईन ने 2012 में तलाक के लिए प्रस्तुत की गयी अर्जियों के परोक्षण के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि 33 फीसदी तलाक की अर्जियॉ फेसबुक के कारण ही दायर की जाती है। डेली मेल प्रकाशन के ऑनलाइन अखबार के प्रवक्ता मार्क कीनन के मतानुसार फ्लर्ट यानी बिना गम्भीरता से हलके ढंग से प्रेम प्रर्दशन करना या इश्कबाजी करने का सबसे प्रचलित और आसान साधन फेसबुक ही है। 'अमेरिका एकेडमी ऑफ मेट्रिमेनीयल लॉयर्स की राय है कि इस सोशल नेटवर्किंग के कारण ही तलाक की संख्या में बढ़ोत्तरी आयी है। इतना ही नही वैश्विक स्तर पर जीवन का श्वास बन रही नेटवर्क सोसायटी के

कारण सामाजिकता,परस्पर सम्बंध और संपर्क की आवश्यकता नहीं रही। सब कुछ कमरे की चार दिवारी में चल रहा है। एक नयी जीवन प्रणाली अस्तित्व में आ रही है। 'अनामिक ' या वर्चुअल समाज जिसे आभासी समाज भी कह सकते है,बढ़ रहा है। मैने जानबूझकर परदेश की विवेचना की है, क्योकि हमें आयातित चीजें और विचार या जीवन प्रणाली ही अधिक पसंद है।

हम भूल जाते है कि नकल कभी असल नहीं होती। फेसबुक पर मुखदर्शन भी जाली और नकली हो सकता है क्योकि यह प्रत्यक्ष सम्पर्क या दर्शन नहीं हैं परिणामस्वरुप अब सम्बंध टूट रहे है बिना परस्पर सम्बंध या सम्पर्क के 'निवास 'उभर रहे ह अब तो पडोस भी सम्बंध विहीन है हम एक दूसरे के पडोस में रहते है, लेकिन साथ नहों रहते ।

उत्तरः—मैं इस बात से सहमत हूँ कि परिवार व्यवस्था सहजीवन सिखाने वाली पहली पाठशाला है। परिवार व्यवस्था माता पिता से शुरु होती है और पति पत्नि से गुजरते हुये पुत्र पुत्री तक आकर पूरी हो जाती है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि परिवार व्यवस्था की शुरुवात पति पत्नो से होती है। और यदि इसकी शुरुवात पति पत्नो से होती तब तो इसकी टूटन के कारणां में फेसबुक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता था किन्तु माता पिता पति पत्नो और बच्चों को मिलाकर बनने वाले परिवार में टूटन के कारणों में फेसबुक एक कारण होते हुए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं।

परिवार न कही से प्रारंभ होता हें न समाप्त । परिवार सतत सक्रिय इकाई है जो हजारों वर्षों तक निरंतर चलती रहती है। यह अलग बात है कि समय समय पर परिवार विभाजित होकर नये परिवार भी बनाते रहते हैं।

परिवार व्यवस्था को समाप्त करने की शुरुवात वहॉ से हुई जब गॉधी के मरते ही दो ऐसे भारतीय भारत का भाग्य लिखने लगे जिनके नाम तथा सूरत शक्ल छोड़कर कुछ भारतीय नहीं था। भारत परिवार को व्यवस्था की पहली इकाई मानता था तथा समाज को अन्तिम । पश्चिमी जगत तथा समाजवादी व्यवस्था व्यक्ति के बाद सीधे राज्य या समाज से जोड़ देती है। बीच में परिवार की मान्यता नहीं होती । ऐसे भारतीय पण्डित नेहरु तथा भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ परिवार व्यवस्था को अमान्य ही किया बल्कि उन्होने परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के सभी साधन बना दिये। परिवार एक ऐसी मजबूत इकाई है कि जिसके सदस्यों का परिवार में रहते हुए सामूहिक अस्तित्व होता है, पृथक नहीं। परिवार अपने आप में एक संगठन है जिसमें संगठन का अनुशासन अनिवार्य है। मै आज तक नहीं समझा कि परिवार का कोई सदस्य बिना पारिवारिक सहमति के किसी अन्य संगठन की सदस्यता कैसे ले सकता है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि महिला सशक्तिकरण का नारा परिवार तोड़क है या नहीं?चाहे गॉधीवादी हों या वामपंथी चाहे कोई नेता हो अथवा धर्म गुरु। सभी चाहे ना समझी में या षड़यंत्र के अन्तगत महिला सशक्तिकरण जैसे असामाजिक प्रयत्न को सामाजिक कार्य घोषित करने में गर्व महसूस करते हैं। बालिग मताधिकार भी ऐसा ही घातक प्रयत्न था। जब हमारा एक सांसद लाखों मतदाताओं के स्थान पर संसद में प्रतिनिधित्व कर सकता है, मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्रिमंडल में रहते हुए बाहर में स्वतंत्र विचार नही रख सकता उसी तरह बालिग मताधिकार की जगह परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक मुखियॉ को नियुक्त करते तथा निर्वाचित मुखियॉ ही आगे वोट देता जिसके वोट परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर गिने जाते। परिवार की सम्पत्ति में भी सबका समान हिस्सा समान अधिकार होना चाहिये था। परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति में सबका समान हिस्सा होने से महिलाओं को पृथक सम्पत्ति अधिकार की बात नहीं उठती।

इसी तरह परिवार को वृद्ध और जवान में बॉटना भी घातक है। वृद्धाश्रम जैसी अवधारणा पूरी तरह घातक है। जो वृद्ध परिवार छोड़कर अपना आर्थिक हिस्सा लेकर बाहर निकले उन्हें आप ग्राम परिवार में रख सकते है,अन्यथा युवा प्रोत्साहन,वृद्धा सहायता जैसे विचार घातक हैं। मेरे विचार में फेसबुक की परिवार तोड़ने में बहुत माम्ली भूमिका है। बड़ी भूमिका है बालिग मताधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार,महिला सशक्तिकरण, युवा प्रोत्साहन, वृद्ध सहायता आदि की। आप जैसे समाज सुधारक जितना परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न करते हैं उससे कई गुना अधिक घातक परिणाम राजनैतिक विचारधारा का होता है। मैं चाहता हूँ कि आपके प्रयत्नों के साथ साथ परिवार तोड़क राजनैतिक प्रयत्नों के विरुद्ध भी जनमत बनना चाहिये।

(4)हितेश कुमार शर्मा,बिजनौर, उत्तरप्रदेश ज्ञान तत्व—8199

विचार—देश में बलात्कार की घटनाऍ लगातार बढ़ रही है। ज्यों ज्यों समाधान के प्रयत्न बढ़ रहे हैं त्यों त्यों ऐसी घटनाऍ तेजी से या तो बढ रही हैं या प्रकाश में आ रही हैं। मैंने इस विषय में बहुत सोचा तो महसूस हुआ कि समाधान गलत दिशा में हो रहें है। बलात्कार वृद्धि के तीन प्रमुख कारण है—(1)न्यायपालिका की प्रभाव हीनता। न्यायपालिका ऐसे अपराधियों में भय का संदेश देने में असफल है। मुकदमें लम्बें चलते हैं तथा किसी न किसी तकनीकी कारण का सहारा लेकर अपराधी छूट जाता है।(2)महिलाओं में पाश्चात्य संस्कृति का विकास।महिलाये अपनी सुरक्षा के प्रति जरा भी सतर्क न रहकर वे रात तक या तो अकेली या अपने व्वाय फ्रेन्ड के साथ घूमती रहती हैं। ऐसी स्थिति में बलात्कार की घटनाओं का बढ़ाना स्वाभाविक है।(3)युवाओं में पारिवारिक सामाजिक भय का अभाव। अब युवकों में उच्श्रृखलता बढ़ती जा रही है। न परिवार का अनुशासन है न सामाजिक प्रतिष्ठा का भय।ऐसी स्थिति में यदि उसे उत्तेजना और एकान्त एक साथ मिल जाता है तो वह अपने को रोक नहीं पाता। हमारे राजनेता इन कारणों पर विचार किये बिना ही बलात्कार रोकना चाहते है जो संभव नहीं। इस संबंध में आपका क्या विचार है?

उत्तरः— भारत में बलात्कार की घटनाऍ तेजी से बढ़ी है। इसके बढ़ने में वे कारण महत्वपूर्ण नहीं जो आपने बताये हैं। मेरे विचार में प्रमुख कारण है करीब दो प्रतिशत महिलाओं का परिवार व्यवस्था से मोह भंग होना।ये महिलाऍ अपनी शारीरिक भूख मिटाने के निमित्त किसी खूंटे से बंध कर नहीं रहना चाहतीं। इस इच्छा पूर्ति के लिये उन्हें सबसे अधिक सहायक है महिला सशक्तिकरण की आवाज मजबूत करना। हमारे अधिकांश राजनेताओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर दो सुविधाऍ एक साथ मिलती है।(1) वोट(2) अपनी शारिरिक भूख मिटान में आने वाली बाधाओं का कमजोर होना। ऐसे पुरुष और महिलाऍ सम्पूर्ण भारत में दो प्रतिशत से भी कम हैं किन्तु राजनीति, मीडिया,सामाजिक संगठन से बढ़ते बढ़ते धार्मिक संगठनों तक इनका प्रभाव है। ये पुरुष को उपभोक्ता तथा

नारी को उपभोग्य प्रमाणित करन में जी जान लगाए हुए हैं और ऐसे असत्य प्रसार में इनके साथ ऐसे दो प्रतिशत पुरुष और महिलाएँ तक साथ मिलकर काम कर रहें हैं। जबकि सच्चाई यह है कि काम वासना पूर्ति के मामले में महिला और पुरुष एक दूसरे के समान रुप से पूरक हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि महिला या पुरुष में से कोई एक दूसरे का उपभोग करता हो। महिला सशक्तिकरण के कारण महिला और पुरूष के बीच की दूरी घट रही है। सरकारी नौकरी मे अथवा राजनीति मे अथवा अन्य स्थानो पर भी इस दूरी को घटाने का लगातार प्रयास हो रहा हैं। इस दूरी के घटने से ऐस दो प्रतिशत स्त्री पुरूषो को एक साथ होने मे सुविधा हो जाती है ।

मुझे तो आश्चर्य है कि कुछ ना समझ लोग बिना विचारे महिला सशक्तिकरण की हॉ में हॉ मिलाने लगते है। ऐसे परिवार तोडक प्रचार का विरोध होना चाहिये। दो प्रतिशत ऐस स्त्री पुरुषों को कोई अधिकार नहीं कि वे अठ्ठानवें प्रतिशत परिवारिक परिवारों पर अपने कानून थोप सकें।

मुझे तो इस समस्या का एक ही समाधान दिखता है कि परिवार के लोगों को अपने पारिवारिक निर्णय की स्वतंत्रता हो।जो परिवार महिला और पुरुषों के बोच दूरी घटाने के पक्षधर है उन्हें पूरी स्वतंत्रता हो कि वे खुली घूमें। कोई अन्य उन पर कोई रोक न लगावे। दूसरी ओर जो परिवार महिला और पुरुष के बीच दूरी बढ़ाने के पक्षधर हों उन्हें भी छूट हो। इन पर भी कोई कानून बाधा न पैदा करे। परिवार सशक्तिकरण समाज सशक्तिकरण ही समस्या का समाधान है।

दो दिवसीय जन जागरण मंथन सम्मेलन का समापन

रामानुजगंज। व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी का दो दिवसीय जन जागरण मंथन सम्मेलन का आज यहॉ समापन हुआ। ध्यातब्य है कि यह सम्मेलन व्यवस्थापक (व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी) द्वारा नालंदा विश्व विधालय के पूर्व आचार्य डॉ0 ईश्वर दयाल के नेतृत्व मे संचालित अखिल भारतीय जन जागरण यात्रा के प्रथम सत्र के समापन के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह यात्रा विगत सात अक्टूबर को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई 25 दिसम्बर को यहॉ पहुॅची थी। जन जागरण जत्था के यहॉ पहुॅचने पर आचार्य पंकज (ऋषिकेश) तथा श्री राकेश शुक्ल (दुर्ग म0प्र0) के नेतृत्व में नगर के गणमान्य जनों ने उसका स्वागत किया।

इस अवसर पर सत्यनारायण धर्मशाला, रामानुजगंज के प्रांगण में आयोजित जन जागरण मंथन सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए व्यवस्थापक के प्रेरणा स्त्रोत श्री बजरंग मुनि ने कहा कि स्वान्त्रोत्तर भारत म परिस्थितियां दिन–दिन जटिल से जटिलतर होती जा रहीं हैं। देश राजनैतिक नेताआे, नौकरशांहो कारपोरेट घरानों और अपराधी तत्वों का चारागाह बनकर रह गया है। आम जनता की परिवर्तन की आकांक्षा हर बार सत्ता परिवर्तन बनकर रह जाती है। उन्होने जोरदार शब्दो सें आम जन से व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया।

जन जागरण दल के संयोजक डा0 ईश्वर दयाल ने उन चार बिन्दुओ पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जिसका संदेश देता दल देश के विभिन्न भागों में घुम रहा हे। वे चार बिन्दु है–

1 परिवार, गांव और जिले को संवैधानिक अधिकार

2 संसद की उत्श्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद को स्थापना

3 मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार (राईट टू रिकाल)

4 प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रूपये राष्ट्रीय आय में से लाभांश के रूप मे देने का प्रावधान

उक्त चार बिन्दुओ पर विश्लेषण ए टू जेड टेलीविजन पर सीधे प्रसारित भी किया गया । प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह ने ग्यारह हप्ते तक दस प्रान्तों मे चली जन जागरण यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर दस राज्यों में दस हजार कि0मी0 की यात्रा हुई नब्बे बैठकें हुई और दस हजार जनता से सीधा संवाद हुआ।

ग्राम सभा सशक्तिकरण सत्रा में डा0 राकेश शुक्ल (दुर्ग) के नेतृत्व में रामराज गुप्ता व सुनील विश्वास ने रामानुजगंज के पंद्रह वार्डो और निकट के एक सौ तीस गांवों में चलने वाले ग्राम सभा सशक्तिकरण के प्रयोगो, बाधाओं और दशा दिशा पर विस्तार से प्रकाश डाला

यात्रा दल के सदस्यों ओम प्रकाश दुबे (नोएडा), छबील सिंह सिसौदिया (उ0प्र0), अर्थ शास्त्री, रौशन लाल ने यात्रा के खटटे–मीठे अनुभव सुनाये। आगामी यात्रा के लिये पूरे देश को आबादी और क्षेत्र के आधार पर सघन, सामान्य और विरल क्षेत्रो मे बॉटकर यात्रा और संगठन करने का निश्चय किया गया। सघन क्षेत्र में दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र रखे गये हैं जहॉ देश की लगभग एक तिहाई आवादी रहती है। सामान्य क्षेत्र मे शेष हिन्दी भाषी क्षेत्र जम्मु कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र रखे गये है। शेष दक्षिण और पूवोत्तर भारत को विरल क्षेत्र में रखा गया हैं। आगामी दो वर्षो मे इन क्षेत्रो मे व्यवस्थापक का संगठनात्मक ढांचा खडा करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

आगामी यात्रा मध्य फरवरी या मार्च से प्रारंभ होने की संभावना है।

देश के विभिन्न भागो से से आये प्रबुद्ध जनों सर्व श्री रामकृष्ण पौराणिक, उज्जैन, आचार्य राजकिशोर शास्त्री (मेरठ), सुधीर तालियान (उत्तर प्रदेश), आफताब, अयुब वारी (जम्मु काश्मीर), संतोष माखरीया (झारखंड), चन्द्रशेखर शशि (सुपौल), आदित्य कुमार सिंह (दरभंगा), डा0 जैनेन्द्र कुमार शुक्ल प्रभात (गापालगंज), बाल किशोर त्यागी, ऋषिपाल सिंह यादव (सम्भल), आदि ने भी अपने विचार रखे और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सतत कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

आचार्य पंकज (ऋषिकेश) ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर सर्व श्री गणेश रवि (डालटनगंज), मो0 सनाउल्लाह (छत्तीसगढ), सीर अहमद मोनाजीर अहमद (जम्मु कश्मीर), मो0 मुस्तफा (लक्खी सराय), रमेश कुमार चौबे (पटना), कामेश्वर प्रसाद (राजगीर) आदि उपस्थित थे।

व्यवस्थापक
व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी

व्यवस्थापक की जन जागरण यात्रा–एक दृष्टि–

व्यवहार जगत में जीवन का व्यवस्थागत प्रबंध सभ्यता का प्रतीक है। जीवन एकांगी नही हो सकता। प्राकृतिक एंव भौतिक आवश्यकतायें व्यक्ति को परस्पर रूप से अन्य पर निर्भर करतीं हैं। जिसका परिणाम समाज नाम की संस्था के निर्माण के रूप मे हमारे सामने आता है। प्राकृतिक एवं भौतिक दोनों दृष्टिकोण से व्यवस्था जीवन की आवश्यकता है। यद्यपि आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था के स्वरूप की विवेचना कई दृष्टिकोण से की जा सकती है। जैसे कि तत्काल में हमारा विषय भारत की राज्य व्यवस्था पर केन्द्रित है। जिसके सत्ता लोलुप प्रकार ने समाज की दशा और दिशा दानो को ही पतनोन्मुख कर दिया है। वर्तमान का भारतीय लोकतंत्र समाज को व्यवस्थित करने का प्रकार नही है बल्कि यह समाज पर शासनगत नियंत्रण करने का प्रकार है। इस विषय में छत्तीसगढ राज्य के रामानुजगंज (बलरामपुर) में व्यापक अनुसंधान होते रहे हैं । स्थापित व्यवस्था की विषय वस्तु को लेकर किये गये अनुसंधान के निष्कर्ष स्वरूप व्यवस्था के ढांचे में निहित खामियों के उन्मूलन हेतु हम एक आंदोलन की रूप रेखा समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आंदोलन के चार सूत्र निम्न प्रकार हैं–

1 परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार।
2 संसद की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना।
3 मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार।
4 प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रूपये राष्ट्रीय आय से लाभांश देने की व्यवस्था ।

ये चार सूत्र किस प्रकार स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन की भूमिका तैयार करेंगे समाज के सामने इस विषय की विवेचना करने हेतु व्यवस्थापक संस्था के तत्वाधान मे प्रथम चरण में दिनांक 7/10/2014 से 24/12/2014 तक देश के दस राज्यो के करीब एक सौ बीस स्थान पर सम्पर्क यात्रा की शुरूआत वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से हुई। यात्रा की शुरूआत के समय इस आंदोलन के प्रेरणा श्रोत श्री बजरंग मुनि ने यात्रा मे शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा समाज को यह संदेश देने हेतु विदा करते हुए अपने उदबोधन मे कहा– मै यह यात्रा किसी सरकार, राजनीतिक दल या संगठन के विरूद्ध नहीं है। हमारे द्वारा लोगो को दिया जाने वाला संदेश यह है कि हम लोग उस स्थापित व्यवस्था के ढांचे मे ही परिवर्तन चाहते है जिसकी खामियां समाज के कष्टों की उत्पत्ति व विस्तार का कारण हैं। हम व्यवस्था चलाने वाले व्यक्तियों के परिवर्तन की बात नही करते, वह जनता द्वारा निर्वाचित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमारे परिवर्तन का उद्देश्य तो व्यवस्था के ढांचे मे निहित है। जिन चार सूत्रो के आधार पर हम यह आंदोलन करने का विषय समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे है। उनके आधार पर परिवर्तित होने वाली या नई बनने वाली विधियां व्यवस्था (शासन) को राज्य सापेक्ष के स्थान पर समाज सापेक्ष बना देंगी। वाराणसी से शुरूआत के बाद यात्रा का पहला पडाव उत्तर प्रदेश के बिल्थरा रोड मे श्री जे0 पी0 सिंह के तत्वाधान मे हुआ। यहां पर यात्रा मे शामिल वक्ताओं ने व्यवस्था के लोक नियंत्रित ढांचे के गुण धर्म की विवेचना की तो साथ मं स्थानीय कार्यकर्ताओ के सामने यह भी प्रश्न उठाया कि भारत श्रम बाहुल्य देश हैं। यदि श्रम की प्रतिस्पर्धी अर्थात कृत्रिम उर्जा श्रम से सस्ती रहेगी तो भला भारत की आर्थिक असमानता तथा विपन्नता का उन्मूलन कैसे हो सकेगा? इस कम में आगे बढते हुए यात्रा के कार्यकर्ता मउनाथ भंजन, सुजिया मउ (जौनपुर), जंगीगंज (भदोही) जहानाबाद (फतेहपुर) होते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले मे पहुँचे। यूं तो यात्रा के प्रत्येक केन्द्र पर आंदोलन के विषयों तथा स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओ पर चर्चा हुई , लेकिन बुंदेल खंड की स्थिति देख–समझकर जन जागरण यात्रा के कार्यकर्ताओं के मन मे यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या लोक स्वराज्य के इस आंदोलन की पृष्ठभूमि का बीज बुंदेलखंड की जमीन पर ठीक उसी प्रकार बोया जा सकेगा जिस प्रकार बिहार के चंपारण जिले मे गांधी का ''निलहे गोरों'' के विरूद्ध प्रसिद्ध ''नील आंदोलन'' हुआ था । व्यवस्था की स्थापना का उददेश्य समाज के संतुलन मे निहित है। लेकिन क्या व्यवस्था की स्थापना का सिद्धान्त राज्य को ऐसा निरंकुश बना देता है कि वह समाज के अधिकारों का भक्षण शुरू कर दे। प्राकृतिक सम्पदायें सर्वथा समाज को प्राप्त होतीं हैं, राज्य को नही। प्राकृतिक एंव भौगोलिक स्थितियों–परिस्थितियों को समाज सदैव जीवन के अनुकूल बनाता है और जीवन के क्रमिक विकास मे उनका नियोजन करता है। क्या राज्य को व्यापार तथा राज्यगत भ्रष्टाचार को बढावा देने की दृष्टि से समाज को ऐसा करने से रोक देना चाहिए। बुंदेलखंड के लोगो के सामने आज ऐसी कई शासन जनित समस्यायें हैं जिनका निवारण इस आंदोलन के सूत्रो के द्वारा किया जा सकता है और देश की समाज तथा राज्य व्यवस्था के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

यात्रा अपने कम मे बढते हुए खैरागढ व रोझौली (आगरा) से राजस्थान के भरतपुर व अलवर, हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद से नोएडा तथा गाजियाबाद जिले के रावली कलां गांव मे पहुँचीं। यहॉ पर लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि लोकतंत्र मे सरकार चलाने वाले नुमाइंदे का चयन तो जनता ही करती है। जनता जिस प्रकार के लोगों का चुनाव करती है, वैसा ही परिणाम लोगों के सामने आता है। देश मे व्यवस्था परिवर्तन नही, बल्कि व्यवस्था बुरे लोगों से मुक्त होनी चाहिए। तब सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जायेगा।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यात्रा दल के वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में देश पर किसी व्यक्ति या दल का शासन नही होता, बल्कि संविधान का शासन होता है। संविधान की रीति–नीतियों के अनुसार ही व्यवस्था का कार्यान्वयन होता है। यदि संवैधानिक विषय वस्तु अपनी कार्यकारी इकाईयों को व्यवस्था का समुचित कार्य करने के लिये बाध्य नही करती है, उल्ट ये

व्यवस्थागत इकाईयां अपने अपूर्ण और यथार्थ हीन प्रावधानो के द्वारा नियंत्रण हीन शक्ति प्राप्त करके नीतिहीन कार्य करते हैं तो व्यवस्था (राज्य) को उसके मूल के प्रति जबाब देह बनाने की आवश्यकता हैं ।

आगे यात्रा दल मेरठ जिले के भूनि, डाहर, कुरथल, कालंद, मैनापूठी से होते हुए हरियाणा के करनाल जिले के सालवन गांव तथा कैथल शहर में बैठक करते हुए पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा कस्बे मे पहुॅची। राजपुरा मे भारतीय राज्य व्यवस्था की कर प्रणाली एवं सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन की अजब बानगी स्थानीय कार्यकर्ताओ द्वारा दल के सामने प्रस्तुत की गयी। किसी भी राज्य व्यवस्था द्वारा कर प्रणाली के नियमन का उद्देश्य व्यवस्था के आर्थिक प्रबंध मे निहित होता है। पंजाब प्रांत की सरकार ने पांच जिलों मे व्यापार पर कैंसर टैक्स लगाया है तथा लोगो द्वारा अपने खेतो मे धान के पुआल को जलाने पर रोक लगाते हुए यह कानूनी प्रावधान किया है कि जो किसान खेत मे पुआल जलाते हुए पकडे जायेंगें उन पर पचास हजार से एक लाख रूपयें तक जुर्माना लगेगा। प्रश्न उठता है कि क्या यह कैंसर टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता से वसूल नही किया जायेगा! क्या राज्य की ऐसी कठोरता समाज का समुचित प्रबंध कर सकती है? आंदोलन के सूत्रो पर प्रकाश डालते हुए यात्रा दल के वक्ताओं ने कहा कि परिवार, गांव व जिले को यदि संवैधानिक अधिकार मिल जायेगे तो राज्य, समाज के विषयों मे अनावश्यक हस्तक्षेप नही कर सकेगा।

यात्रा दल मलेर कोटला (संगरूर), नैनेवाल, (बरनाला) पहुंचे । यहॉ पर यात्रा दल की बैठक एन आर आई श्री दर्शन सिंह नैनेवाल जी के तत्वाधान मे हुई। उन्होने विदेशो मे प्राप्त अनुभवो के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की तुलना करते हुए कहा कि भारत मे लोकतंत्र का माहौल ही नही है। भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के अनुसार उनकी तुलना समिचीन ही प्रतीत होती है। यहां बैठक करते हुए यात्रा दल जम्मू पहूॅचा। यात्रा जम्मू से खेडाचक (हिमाचल प्रदेश) हरियाणा के नारायणगढ से उत्तराखंड के देहरादून ऋषीकेश, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अम्बौली, देवबंद, दल्हेडी से शामली, जिले के कंडेला, मन्डेठ कला, दुल्लाखेडी में बैठक करते हुए पिलखुआ (हापुड), दौराला (मेरठ), हापुड शहर, शाहपुर फगौता (हापुड), गाजियाबाद, बनबोई व बनैल (बुलंदशहर) की बैठक मे यात्रा का संदेश देते हुए एटा पहुॅची। यात्रा अगले गन्तव्य कासगंज शहर से सहावर (कासगंज) मे एक विशुद्ध पंथ निरपेक्ष भद्र जन डा0 इस्लाम अहमद फारूखी के निवास पर पहुंची । सहावर मे स्थानीय कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के 130 गांवो मे ग्राम स्वराज्य की स्थापना हेतु चलाये जा रहे ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान पर स्थानीय कार्यकर्ताओ से विशेष चर्चा हुई। यात्रा दल अपने निर्धारित कार्यकम के अनुसार आगे बढते हुए लोकस्वराज्य के लिये समर्पित कार्यकर्ताओं श्री बहादुर सिंह यादव व श्री ऋषिपाल सिंह यादव के कार्य क्षेत्र जिला बदायुं व सम्भल जिलो मे पहुॅची। इन जिलो के उझानी, सहसवान, बबराला, धनारी, भगनगर, राजपुर, कमालपुर–खानूपुरा, मंडावली, रसूलपुर, बहरामपुर, केन्द्रो पर यात्रा दल के कार्यकर्ताओ की जनता के साथ बैठके हुई। इन बैठको मे एक महत्वपूर्ण विषय जो उबरकर सामने आया वह यह रहा कि क्या स्वराज्य का दृष्टिकोण समाज के परिवेश से राज्यगत सत्ता का अनर्गल प्रभाव समाप्त कर देगा? व्यक्ति मूलतः सत्ता के केन्द्र को अपने लिए सुरक्षा और न्याय के दाताके रूप मे स्वीकार करता है। इस समाज मे विरले व्यक्ति ही इस मानसिक द्वंद से मुक्त होते हैं कि किसी राज्यगत सत्ता केन्द्र के अभाव में व्यवस्था की स्थापना भी संभव है। लोकतंत्र में भी व्यक्ति राज्य के शासन गत स्वभाव को नहीं नकार पा रहा है। अलबत्ता इन बैठकों का परिणाम यह अवश्य आया कि ठेठ साधारण जनता भी उस परिवर्तन के लिए लालायित दिखी जो उसे सत्ता की नाकारा तासीर से सदैव के लिए मुक्ति दिला सके। इस कम मे व्यवस्था की जन जागरण यात्रा आगे बढते हुए उत्तराखंड के बाजपुर दिनेशपुर व रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) बसौली (अल्मोडा) बागेश्वर शहर व भनार (बागेश्वर) में हिमालय पर्वत की उॅची चोटियों तक पहूंची । इस उचाई से अपने केन्द्र की ओर लौटते हुए पहली बैठक बरेली (उत्तर प्रदेश) मे हुई। बरेली मे कुछ युवाओ ने यात्रा दल से यह प्रश्न किया कि क्या इस आंदोलन से प्रतिष्ठा पाकर आंदोलन के कार्यकर्ता परम्परागत राजनीति को अपना पेशा बनाकर स्वार्थ सिद्धि तो नही करेगे। इस विषय मे दल के वक्ताओं ने कहा कि हमारे आंदोलन का मकसद राजनीतिक पद–प्रतिष्ठा को ऐसा बना देना है कि कोई भी नेता या सरकारी मशीनरी के लोग पद से प्राप्त शक्ति को निहित स्वार्थो मे प्रयोग ही न कर सके। कुछ अपरिहार्य कारणों से हमें शाहजहॉपुर व लखीमपुर खीरी जिलो की बठक निरस्त भी करनी पडी। इससे आगे यात्रा छोटी पुरवा (बाराबंकी) व बाराबंकी नगर , कर्नलगंज, (गौंडा), परसहर, (खलीलाबाद), खडडा, बोदरवार (कुशीनगर), पगरा, (देवरिया), सतहवां, (गोरखपुर), भोरे–गोपालगंज, (बिहार), गोपालगंज शहर, मुजफ्फरपुर शहर, रोसडा, (समस्तीपुर), सहरसा , सुपौल, कतारी व राजगीर (नालंदा), लक्खीसराय व झारखंड के देवघर होते हुए प्रथम चरण के समापन स्थल रामानुजगंज (बलरामपुर) पहुॅची। यात्रा विवरण के इस विवेचना पत्र मे सम्पूर्ण व्यवस्थापक परिवार विभिन्न केन्द्रो पर मिले जनता के सहयोग व सहभागिता का धन्यवाद करता है और पुनः जनता का यह आह्वान करता है कि हमे व्यवस्था के समाज के प्रतिकूल स्वभाव का उन्मूलन कर देना चाहिए।

जन जागरण यात्राः विहंगमावलोकन

क–आच्छादित राज्यः–उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दिल्ली, बिहार,झारखंड।

ख–आच्छादित जिले–इक्यावन।

ग– आच्छादित दूरी–दस हजार पांच सौ किलोमीटर लगभग।

घ–संपर्कित व्यक्तियो की संख्या–पंद्रह हजार लगभग।

च– यात्रा के प्रतिभागी–आचार्य पंकज (उत्तराखंड), डा0 ईश्वर दयाल (बिहार) , ओम प्रकाश दुबे (नोएडा), रोशन लाल अग्रवाल, (छ0ग0), छबील सिंह शिशौदिया (उ0प्र0), विनोद भाई (महा0), सभापति पाठक (बिहार), नरेन्द्र सिंह (उ0प्र0),

व्यवस्थापक

(व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी)

अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ

बुरी सरकारो की बुराई पायः सभी लोग सदैव से करते आये हैं, लेकिन किसी अच्छी सरकार को हम अपने ऊपर शासन करने दे क्या इसे सभ्यता का कोई प्रतिमान कहा जा सकता है। जीवन व्यवस्थागत रूप से निर्वाह होता है तो इससे परस्पर स्वतंत्रता का पालन सुनिश्चित होता है। लेकिन जीवन पर किन्ही परिस्थितियों मे जितना भी शासन गत प्रभाव बढता है इसकी मौलिक स्वतंत्रता उतनी ही छिन्न–भिन्न होती जाती है। लोक स्वराज्य की परिकल्पना जीवन पर शासन गत नियंत्रण के उन्मूलन का सुलभ प्रकार है। यह परिकल्पना हमारे सामने व्यवस्था के ऐसे ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है जिसके अन्तर्गत हम शासन गत गुलामी से मुक्ति पा सकते है। इस विषय मे व्यवस्थापक एक आंदोलन की परिकल्पना समाज के सामने प्रस्तुत करते है जो समाज को शासन प्रणाली से मुक्त करके लोक स्वराज्य की ओर अग्रसर करती है। आंदोलन की पृष्ठ भूमि निम्न चार सूत्रो पर आधारित है–

1–परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार।

2–संसद की उत्श्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना।

3–मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार।

4–प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रूपये राष्ट्रीय आय से लाभांश देने की व्यवस्था ।

किसी आंदोलन की सफलता के विषय मे यदि सोचा जाये तो यह केवल समर्पित कार्यकर्ताओ एंव नियोजित गतिविधियों के आधार पर प्राप्त नही होती है बल्कि यह आंदोलन की विषय वस्तु में निहित होता है कि वह जनता की हृदय ग्राह्यता एवं हित बद्धता के लिए कितनी बाध्यकारी है। व्यवस्थापक के इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्या ऐसे गुण निहित हैं जो समाज के लिए स्वराज्य प्राप्ति का आधार तैयार कर सके? हम बिन्दुशः विवेचन ऐसा करने का प्रयास करते है।

आंदोलन की पृष्ठभूमि का पहला विषय परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराना हैं । परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकारो की प्राप्ति का अर्थ इन तीनो इकाईयों का राज्य की व्यवस्था में संवैधानिक इकाई के रूप मे स्थापित होना है।इस परिस्थिति में इन तीनों इकाईयों के अधिकार क्षेत्र मे निहित विषयों मे किये गये निर्णय मे कोई भी वाह्य हस्तक्षेप नही हो सकेगा।

आंदोलन की पृष्ठभूमि का दूसरा सूत्र है संसद की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना। लोक संसद की संरचना का प्रस्ताव निम्न प्रकार है–

1– वर्तमान लोकसभा के समकक्ष एक लोक संसद हो। लोक संसद की सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली तथा समय सीमा वर्तमान लोक सभा के समान हो। चुनाव भी लोकसभा के साथ हो किन्तु चुनाव दलीय आधार पर न होकर निर्दलीय आधार पर हो।

2–लोक संसद के निम्न कार्य होगें–

(क) लोक पाल समीति का चुनाव।

(ख) संविधान संशोधन के संसद के असीम अधिकारो को संसद और लोक संसद के रूप मे द्विस्तरीय बनाना।

(ग) सांसद, विधायक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री एवं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संबंधी प्रस्ताव पर विचार व निर्णय।

(घ) राइट टू रिकाल का कोई प्रावधान बनाना ।

(च) लोकपाल समीति के भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत का निर्णय ।

(छ) किन्ही भी संवैधानिक इकाईयों के बीच आपसी टकराव पर निर्णय।

3– लोक सांसद का कोई वेतन नहीं होगा। बैठक के समय भत्ता प्राप्त होगा।

4– लोक संसद का कोई कार्यालय या स्टाफ नही होगा। लोक पाल समीति का कार्यालय तथा स्टाफ ही पर्याप्त रहेगा।

5–यदि किसी प्रस्ताव पर लोक संसद तथा लोक सभा के बीच अंतिम रूप से टकराव होता है तो उसका निर्णय जनमत संग्रह से होगा।

6– लोक संसद किसी भी संवैधानिक इकाई के आंतरिक मामलो मे कोई हस्तक्षेप नही करेगी।

आंदोलन का तीसरा सूत्र–मतदाताओ को जन प्रतिनिधियो को वापिस बुलाने का अधिकार है। किसी भी व्यवस्था की स्थापना का यह सर्वमान्य सिद्धान्त होता है कि नियोक्ता को उसके द्वारा नियुक्त की गई इकाई के निलंबन व पदच्युत करने का अधिकार होता है। क्या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता को उनके पद से च्युत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? मूलतः लोकतंत्र जनता के प्रति जवाब देही के रूप मे अपनी पुष्टी करता है। यदि लोकतंत्र का ढांचा उसकी मर्यादाओ के अनुसार न हो तो उसे लोकतंत्र कैसे कहा जा सकता है? अतः मतदाताओं को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापिस बुला लेने का नैसर्गिक अधिकार है और वह उसे मिलना ही चाहिए।

आंदोलन के ये तीन सूत्र राजनीतिक सत्ता के अकेन्द्रीय करण के विषय मे है। इस आंदोलन का चौथा सूत्र समाज व राज्य के आर्थिक प्रबंधन के विषय में है। यह सूत्र इस प्रकार अभिव्यक्त है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार रूपये राष्ट्रीय आय से लाभांश दिया जाये। यह विषय अनेको प्रकार के प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न करता है। जिनमे मुख्य प्रश्न यह है कि जिस देश की कुल आय इतनी भी न हो कि वह बजटीय घाटे की पूर्ति भी कर सकती हो तो भला राष्ट्रीय आय से जनता को लाभांश देने का क्या प्रश्न है? यह विषय पूंजी के केन्द्रीयकरण, देश की प्राकृतिक सम्पदाओ के गलत दोहन, गलत कृषिनीति जैसे उन बुनियादी कारणो पर आधारित है जो आर्थिक प्रबंधन के अनुकूल नही है। इस विषय में व्यवस्थापक के अर्थशास्त्रियो के पास ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जिन्हे सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार करके ऐसी आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन किया जा सकता है जिससे न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था के बजटीय घाटे की पूर्ती की जा सकती है बल्कि राष्ट्रीय आय से लाभांश भी सरलता पूर्वक और सतत दिया जा सकता है। इस विषय में व्यवस्थापक संस्था सरकार व समाज से व्यापक चर्चा करने के लिये तैयार है। यदि आम जन को उनके नैसर्गिक प्राप्य को सहज ढंग से पाप्त करने से अनुचित ढंग से सडयंत्र पूर्वक रोका जाता है तो

उनके ज्वलित आक्रोस के विस्फोट सबकुछ जलाकर राख कर राख कर देगा। व्यवस्थापक उक्त चारो सूत्र के आधार पर व्यापक जन आंदोलन का आह्वान करता है।

प्रवक्ता–नरेन्द्र सिंह
व्यवस्थापक
(व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी)
अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ

मोदी से उम्मीदे, तवलीन सिंह

गये साल के आखिरी दिनों मे मैने गलती से गलतफहमियां पैदा की उन लोगो म, जिनके राजनीतिक विचारो से मै कभी सहमत नही हूँ। दो हजार पंद्रह के इस पहले लख मे मै उन गलत फहमियों को दूर करना चाहती हूँ। हुआ यह कि मै कुछ महिनो से ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आर्थिक सुधारां में वह तेजी नही है जो होनी चाहिये थी। उपर से मैने खुलकर हिन्दू कटटर पंथियों का विरोध किया। इससे मेरे बारे मे समाजवादी, मार्क्सवादी, काग्रेस वादी और सोनियांवादी लोग कहने लगे कि मै मोदी भक्त अब नही रही । इस टोली को मै शुरू मे ही कहना चाहूँगी कि मै भक्ति किसी की नही करना पसंद करती हूँ, भगवान की भी नही। लेकिन मैने नरेन्द्र मोदी का समर्थन जरूर किया है। वह इसलिये कि मुझे विश्वास है कि वे इस बेहाल गरीब देश मे परिवर्तन और विकास ला सकते है। इस आधार पर यह कह रही हूँ कि मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होने एक नई आर्थिक भाषा बोलने को हिम्मत दिखाई है। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होने खुलकर कहा है कि सरकार का काम नही है बिजनेश करना। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होने बार बार कहा कि भारत के गरीब होने का एक भी कारण नजर नही आता । मेरा अपना मानना है कि टूरिज्म को ही अगर गरीबी हटाने का औजार हमने माना होता तो हमारे सबसे गरीब राज्य आज अमीर हो गये। और इन्ही चीजो की जरूरत इस देश के आम आदमी को भी है । मोदी ने खुद कई बार कहा है कि टुरिज्म मे निवेश करने से कई किस्म के लोगो के पैसे बनते है। चाय वाले भी पैसा बनाते है। और जब चाय वाले पैसा बनाते है तो मुझे बहुत आनंद आता है। टुरिज्म म अगर पूर्व प्रधानमंत्रीयों ने निवेश नही किया है तो इसलिये कि उनकी नजर मे समाजवादी आर्थिक नीतियों के तहत खैरात बाटने से ही गरीबी हटती है। कांग्रेस पाटी के बडे नेता अक्सर समाजवादी रहे है। और इनमे से सबसे बडे समाजवादी थे जवाहर लाल नेहरू । उनकी आर्थिक नीतियों का आधार था कि धन पैदा करने के तमाम औजार और रोजगार देने के अवसर भी सरकार के हाथो मे होने चाहिये । उनके समय ज्यादातर दुनियां भी इसी तरह सोचा करती थी क्योकि उस समय सोवियत युनियन की हकीकत लोहे के पर्दे के पीछे ढकी हुई थी। यह पर्दा गिरने लग गया था 1989 मे जब बर्लिन की दीवार गिरने लगी थी । अगले कुछ वर्षो मे सोवियत युनियन खुद टूटने लगा । गलत आर्थिक नीतियों के कारण इसका असर पूर्वी युरोप के हर मुल्क मे दिखा। भारतीय वामपंथी लेकिन कटटर मिजाज क है। सो उन्होने इन तब्दीलियों को बिल्कुल अनदेखा किया। लकीर के फकीर बने रहे ह। कागेंस पार्टी को समस्या यह भी थी कि जिस विचारधारा को वह नेहरू जी की विरासत मानती थी उसे त्यागे तो कैसे? फिर समस्या यह भी थी कि कि नेहरू गांधी परिवार का पूरी तरह से कब्जा कांग्रेस के आर्थिक और राजनीतिक सोच पर था। भारत की गरीबी क्योकि दूर नही हुई सो खैरात बाटने की आदत डाल ली। इस परिवार के सदस्यो ने और पिछले दसक मे सोनियां ,मनमोहन सरकार ने भी खैरात बांटना ही अपनी आदत बना ली। सच यह है कि हमारी आर्थिक नीतियां गलत रही है। वरना कुदरत ने क्या कुछ नहीं दिया है इस देश को?

मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होने इस बात को बार बार स्वीकार किया है कि भारत के गरीब होने का उनको कोई कारण नही दिखता है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए उन्होने योजना आयोग जैसी समाजवादी सस्थाओ को खत्म करने का काम शुरू किया है। दुआ कीजियें कि नीति आयोग बिल्कुल अलग किस्म का आयोग होगा जो अर्थ ब्यवस्था मे दखल देने के बदले नये विचारो नये सोच का केन्द्र बन जायेगा भविष्य मे। मोदी सरकार की आलोचना अगर करने की जरूरत पडी है मुझे पिछले दिनो तो सिर्फ इसलिये कि कटटर पंथी हिन्दुत्व के फैलने के आसार दिखने लगे थे। 2014 के अंतिम महिनो मे साधु साध्वियों के कुछ बहुत ही घटिया स बयान आये। जिनके कारण ससंद मे इतना हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दो मे उनको नकारना पडा। ऐसा करके मोदी जी ने अच्छा किया । लेकिन उन्होने अभी तक धर्मान्तरण पर कुछ नही कहा है। सो रोज सुर्खियो मे रहती है। धर्मान्तरण की कोई नई घटना इतना ही नही आर एस एस के सरसंघचालक भी कुछ जरूरत से ज्यादा बोलने लग गये है। आज कल मोदी जो विकाश व परिवर्तन के मुददे लेकर आये थे वह धुधला से गये है । इसका मतलब यह नही है कि मैने नरेन्द्र मोदी से अपना समर्थन वापिस ले लिया है। अब भी उनके समर्थको म अपने आप को मानती हूँ। क्योकि मुझे चिन्ता है कि अगर मोदी परिवर्तन और विकाश लाने मे नाकाम रहते है तो इस देश के भविष्य मे रेाशनी की छोटी सी संभावना भी दिखनी बंद हो जायेगी ।

उत्तरः– मैं आपके लेख से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पिछले तीस,चालीस वर्षों से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई प्रधानमंत्री आयेगा जो राजनीति और व्यापार को अलग–अलग कर देगा। इसके साथ ही जो भारत से समाजवाद की अन्तेष्टि कर देगा।नरेन्द्र मोदी के रुप में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो दोनों काम कर रहा है। गरीबों को रोजगार के अवसर न देकर सुविधाएँ देना अच्छी राजनीति नही है। नरेन्द्र मोदी इस मामले में भी अच्छा कर रहें है। अब स्पष्ट दिखता है कि पंडित नेहरु परिवार की सत्ता ही नही बल्कि पंडित नेहरु की नीतियों से भी पिन्ड छूट चुका है।

मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि कुछ कट्टरपंथी हिन्दू विकास से ध्यान हटाकर साम्प्रदायिक दिशा में देश को ढकेलने का प्रचार कर रहे है। यह सही है कि मोदी के पूर्व की सरकारें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर चल रही थी। इन नीतियों से पिण्ड छूटना ही हिन्दुओं के लिए पर्याप्त संतोष का आधार था। किन्तु कुछ मुस्लिम प्रवृत्ति के हिन्दू उस दिशा में सरकार

को ले जाना चाहते है जिस दिशा में पिछली सरकार मुसलमानों के पक्ष में चल रही थी। मेरे विचार में यदि मुस्लिम साम्प्रदायिकता बुरी है तो हिन्दु साम्प्रदायिकता उससे भी अधिक बुरी है। बुरे आदमी का बुरा होना बुरा है किन्तु बुरे आदमी की बुराई दूर होने के बाद भी अगर अच्छा आदमी बदले की भावना से बुरा काम करता है तो वह और भी बुरा है। मैं समझता हूँ कि संघ परिवार के लोग मोदी को ठीक राह पर चलने से रोकने का प्रयास नही करेगें और यदि करेंगे तो भारत का हिन्दु इसे सहन नही करेगा।

उत्तरार्ध

व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी

कार्य याजना

व्यवस्थापक (व्यवस्था परिवर्तनअभियान कमेटी) कोई राजनैतिक दल नही आंदोलन है। इसका मूल उद्देश्य सत्ता नही, व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि आम व्यवस्थापक के चतुः सूत्री कार्यक्रमो को जाने , समझ तथा उन्हे समर्थन और सहयोग दे। व्यवस्थापक ने अपनी जन जागरण यात्रा मे जन साधारण से सम्पर्क कर एक ओर तो उन्हे अपी चतुःसूत्री कार्यक्रमो को समझाने समर्थन का प्रयास किया दूसरी ओर उनकी समस्याओं को बहुत निकट से और गहराई से समझने का प्रयास किया। इस क्रम मे अनेक समस्या स्थल मिले, जिन्हे केन्द्र बनाकर जनमत को खडा किया जा सकता है और स्थापित व्यवस्था की नींव को हिलाया जा सकता हैं।

जन जागरण यात्रा के अनुभवो से जन जागरण यात्रा की सार्थकता भी स्पष्ट हुई है और उसे ज्यादा कारगर तथा उपयोगी बनाने की प्रेरणा भी मिली हे। स्पष्ट मानसिकता बनी है कि भविष्य की जन जागरण यात्राएं त्री स्तरीय होनी चाहिये।

1 सघन क्षेत्र

2 सामान्य क्षेत्र

3 विरल क्षत्र

सघन क्षेत्र– दिल्ली के केन्द्र मानकर और भारतीय जन संख्या के एक तिहाई भाग को दृष्टि मे रखकर दिल्ली के आस पास के उत्तर प्रदेश , हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तथा कुछ कुछ विहार के भागो की सघन यात्रा होना चाहिये और लक्ष्य रखना चाहिये कि अगले दो वर्ष मे सदर्भित क्षेत्रो के प्रत्येक ब्लाक मे कम से कम व्यवस्थापक का एक सक्रिय कार्यकर्ता अवश्य है।

2 उत्तर भारत के शेष हिन्दी भाषी प्रदेशों एवं गुजरात के सामान्य क्षेत्र माना जाय। जहां प्रत्येक जिले में अगले दो वर्षो मे एक कार्यकर्ता अवश्य है।

3 देश के बाकी के अहिनी भाषी प्रदेशों के 5–5 संसदीय क्षेत्रो मे कम से कम एक व्यवस्थापक का सकिय कार्यकर्ता आगामी दो वर्षो मे अवश्य बना लिया जाय।

इसके लिये प्रत्येक तरह मे क्षेत्र के लिए सघन सामान्य एंव विरल यात्रा की योजना प्रस्तावित है।

शोक समाचार

आज दिनांक 6/1/2015 को प्रातः यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी के संरक्षक राज सिंह आर्य का एकाएक हृदय गति रूकने से निधन हो गया। राज सिंह जी व्यवस्थापक के संरक्षक तो थे ही साथ ही मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे मार्ग दर्शक थे। उन्होने ही मुझे वानप्रस्थ की प्रेरणा दी थी तथा सन्यास की ओर भी प्रेरित करते थे। राज सिंह जी आर्य समाज के मुर्धन्य विद्वानों मे से एक थे। वे विद्वता के साथ साथ व्यक्ति गत संबंधो का भी पूरा ख्याल रखते थे। राज सिंह जी रामानुज गंज जैसे बीहड जंगली क्षेत्र मे भी दो बार आये और उन्होने दा हजार तेरह मे एक सप्ताह तक रहकर यहां कथा की थी। उनकी क्षति आर्य समाज के लिये तथा समाज के लिये तो महत्वपूर्ण है ही किन्तु व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी के लिये ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके निधन का समाचार सुनकर उनकी अंत्येष्टि मे व्यवस्थापक की ओर से श्री छबील सिंह सिसोदिया तथा रामवीर सिंह श्रेष्ठ ने प्रतिनिधित्व किया।